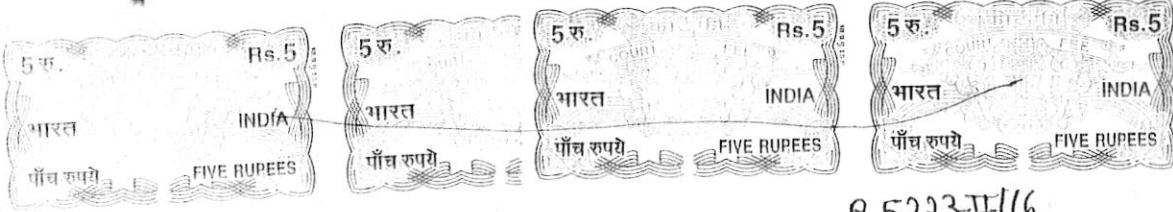


145

उत्तरांचल राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा (म०प्र०)



Rs. 301

R 5223-II/16

1. संत प्रसाद तनय रामाधार उम्र-50 वर्ष, पेशा - खेती, निवासी ग्राम सूर्य तहसील मनगवां जिला रीवा (म०प्र०)



जगदीश प्रसाद तनय स्व० श्री रामाधार उम्र-52 वर्ष, पेशा - खेती, निवासी ग्राम सूर्य तहसील मनगवां जिला रीवा (म०प्र०)

-----निगरानीकर्ता

बनाम्



1. आम जनता द्वारा, बृजेश सिंह तनय स्व० रणबहादुर सिंह निवासी समान तहसील हुजूर जिला रीवा (म०प्र०)

2. अशोक सिंह तनय सन्तोष सिंह निवासी एल०आई०जी० 63/29/335 नेहरू नगर गंगोत्री कालोनी के पीछे रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा (म०प्र०)

-----गैर निगरानीकर्ता

निगरानी कलेक्टर महोदय रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक - 82अ-19/निगरानी/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 16/2/2016 के खिलाफ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू०स०संहिता।

मान्यवर,

मामले के तथ्य निम्न है :-

1. यह कि गैर निगरानीकर्ता क्रमांक - 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय

श्री प्रसाद

BN

न.सिवीकरणगोसा. द्वारा जमानत प्रस्तुत किया गया 13-5-16
रिक्टर कोर्ट रीवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5223-दो / 2016

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-8-2017	<p>आवेदक अभिभाषक ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। कलेक्टर रीवा के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 16-2-2016 की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रश्नाधीन आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में 13-5-16 को प्रस्तुत की गई है। कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन आदेश आवेदक को सुनने के पश्चात पारित किया गया है। आवेदक द्वारा दिनांक 18-2-16 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तथा दिनांक 09-3-16 को आदेश की नकल प्राप्त हो गई थी। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत किये जाने हेतु 60 दिवस का समय प्रावधान है। नकल प्राप्ति हेतु लगे समय को यदि कम कर करने के उपरांत आवेदक को 05-5-16 तक निगरानी प्रस्तुत करनी चाहिए थी, परन्तु उनके द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 13-5-16 अर्थात् 8 दिवस विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है। विलम्ब के समर्थन में म्याद अधिनियम की धारा 5 एवं शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया है। 1996 आर.एन0 257 जिला पंजीयक सहकारी बैंक मर्यादित विरुद्ध काशी प्रसाद गुप्ता में इस न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "विलम्ब के लिए आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत नहीं किया गया - 5 दिन का विलम्ब भी क्षमा नहीं किया जा सकता है।" दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी अवधि बाह्य होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	
	<p>(एस0एस0 अली) सदस्य</p>	